

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II  
(गवर्नेंस) से संबंधित है।

द हिन्दू

04 जनवरी, 2022

## सरकारें पटाखा उद्योग में सुरक्षा प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

तमिलनाडु में पटाखों के क्षेत्र के केंद्र, विरुद्धुनगर जिले के कलाथुर गांव में एक आतिशबाजी इकाई में विस्फोट में नए साल के दिन चार श्रमिकों की मौत, एक उद्योग में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए अथक सतर्कता की आवश्यकता को दोहराती है जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित है। कहा जाता है कि विस्फोट रसायनों के गलत संचालन के कारण घर्षण के कारण हुआ था। जाहिर तौर पर, कार्यकर्ता 2022 में पूजा करने के लिए यूनिट में आए थे।

भले ही अधिकारियों ने यूनिट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है और भारतीय दंड संहिता और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उन्होंने लाइसेंस धारक जैसे उल्लंघन का हवाला नहीं दिया है। इकाई को दूसरों को पट्टे पर देना और अनधिकृत रूप से उत्पादों का निर्माण करना।

इन वर्षों में, जिले में कई विस्फोट हुए हैं और लगातार राज्य सरकारों ने विस्फोटों के कारणों का अध्ययन करने के लिए समितियों का गठन किया है। हालांकि पटाखा उद्योग के कामकाज के तरीके में सुधार भी हुआ है। उदाहरण के लिए, बाल श्रम की सीमा में काफी कमी आई है। लेकिन, सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन और निगरानी के संबंध में, ट्रैक रिकॉर्ड वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।

कलाथुर विस्फोट जैसी घटना को देखने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। आमतौर पर, किसी भी विस्फोट को एक दुर्घटना कहा जाता है, लेकिन इस तरह के उपयोग से अनजाने में उन लोगों की भूमिका खत्म हो जाती है जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था, खासकर तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में पटाखा उद्योग के योगदान को स्वीकार करना होगा। यह क्षेत्र राज्य के पिछड़े क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आठ लाख लोगों को रोजगार देता है।

हालांकि, यह उद्योग को श्रमिकों और समाज के बड़े वर्गों के जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। घटना की किसी भी जाँच में, संबंधित अधिकारियों को फरवरी 2021 में जिले में 20 से अधिक लोगों की मौत के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित आठ सदस्यीय समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को कार्रवाई में बदलने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पंजाब और हरियाणा और मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश के कन्नन, पैनल ने सुझाव दिया था कि विस्फोटक अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि दंड को अब से अधिक कठोर बनाया जा सके, जिसमें मिश्रण, रसायनों को भरने और बनाने सहित संचालन के लिए केवल प्रमाणित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके।

रंग पैलेट, और विभिन्न इकाइयों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करना। उद्योग के कामकाज में सुधार के लिए विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए।

### संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

- प्र. हाल ही में किस राज्य में नए साल पर पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना हुई है?
- (क) कर्नाटक  
(ख) तमिलनाडु  
(ग) उत्तर प्रदेश  
(घ) ओडिशा

### Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Recently in which state there has been an accident in the cracker factory on New Year's Eve?
- (a) Karnataka  
(b) Tamil Nadu  
(c) Uttar Pradesh  
(d) Orissa

### संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्र. 'भारत में खतरनाक श्रेणी वाले उद्योगों में सुरक्षा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के स्तर पर कमियां मौजूद हैं।' तमिलनाडु के पटाखा उद्योग के विशेष सन्दर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ( 250 शब्द )
- Q. There are gaps in the level of implementation of safety protocols in hazardous industries in India. Examine this statement with special reference to the cracker industry of Tamil Nadu.  
(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।